लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1096

17 दिसंबर, 2018 को उत्तर के लिए

इस्पात की खपत

1096. श्री शेर सिंह गुबायाः

श्री के. परसुरमनः

श्री रवीन्द्र कुमार रायः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत को बढ़ावा देने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार का घरेलू इस्पात की खरीद हेतु सरकारी उपक्रमों के लिए प्रोत्साहन नीतियां घोषित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में इस्पात की खपत को बढ़ावा देने हेतु मंत्रालयों और संबंधित सरकारी उपक्रमों के साथ की गई बातचीत का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क): सरकार ने देश में प्रति व्यक्ति इस्पात खपत को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए हैं:-

(i) परियोजनाओं की डिजाइनिंग के लिए सामान्य वित्तीय नियम, 2017 में जीवन चक्र लागत के सिद्धांत की शुरुआत की गई।

(ii) सरकार ने राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 और सरकारी खरीद में घरेलू विनिर्मित लोहा एवं इस्पात उत्पादों (डीएमआई एंड एसपी) को वरीयता प्रदान करने के लिए नीति का क्रियान्वयन किया है। डीएमआई एंड एसपी नीति, अधिसूचित इस्पात उत्पादों को 15% का न्यूनतम मूल्य संवर्धन प्रदान करती है जिन्हें अधिमान्य खरीद के तहत शामिल किया गया है।

(iii) इस्पात मंत्रालय के अधीन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) इस्पात का उत्पादन करने वाले केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है तथा इस्पात मंत्रालय के तत्वावधान के अधीन इंस्टिट्यूट फॉर स्टील डेवलपमेंट एंड ग्रोथ (आईएनएसडीएजी) नामक संगठन ने भी प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया है। इन प्रयासों में ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यशालाओं का आयोजन, इस्पात की उपयोगिता के विषय में जागरुकता का सृजन, राजमिस्त्रियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन इत्यादि शामिल हैं। आईएनएसडीएजी ने ग्रामीण लोगों के लिए इस्पात सघनता वाले कम लागत के घरों, आंगनबाड़ी केन्द्रों, पंचायत हॉल तथा सामुदायिक शौचालयों इत्यादि के डिजाईन को विकसित किया है।

(ख): जी नहीं।

(ग): उपरोक्त (ख) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

****